दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 26 अगस्त 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 326

महत्वपूर्ण एवं खास

अब सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे अफगान नागरिक

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही अफगान नागरिकों के लिए खासतौर पर ई-इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा अब अवैध हो गए हैं। हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए है। यानी पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, आदि अब अवैध हो गए हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के कब्जे के दो दिन बाद ही भारत ने इस ई-इमरजेंसी वीजा का ऐलान किया था। अधिकारियों ने बताया था कि अफगानिस्तान में भारत के मिशनों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में अर्जियों की जांच की जाएगी। शुरुआत में ये वीजा छह महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अर्जियों पर कार्रवाई करते और अफगान नागरिकों को वीजा देते हुए सुरक्षा मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इस वीजा के लिए सभी धर्मों के अफगान नागरिक आवेदन दे सकते हैं।

उच्च न्यायालय अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर दो हफ्तों में दे निर्णयः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर वह दो सप्ताह के भीतर निर्णय करे। भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर में लाया गया था। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रह चुके अस्थाना को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने से चार दिन पहले, 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर कार्यकाल एक साल का होगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को थोड़ा और समय दिया जाए क्योंकि सरकार को वहां लंबित याचिका पर अपना जवाब देना है।

176 करोड़ की आईटीसी धोखाधड़ी में दो और लोग गिरफ्तार

नईदिल्ली (आरएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) खुफिया महानिदेशालय की गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई, हरियाणा ने 176 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले का भंडाफोड़ किया हैं जिसमें इन बिलों को संजय गोयल मालिक मेसर्स रेडामेंसी वर्ल्ड और दीपक शर्मा ने पेश किया था। दीपक शर्मा ऐसी आठ कंपनियों के वास्तव में नियंत्रक हैं जो अस्तित्व में ही नहीं थी। इस मामले में क्षेत्रीय इकाई ने संजय गोयल और दीपक शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच के दौरान दो और प्रमुख व्यक्तियों मनीष मोदी और गौरव अग्रवाल का नाम भी उभर कर सामने आया है। इस मामले की विस्तृत जानकारी के आधार पर क्षेत्रीय इकाई ने मनीष मोदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट निवासी पीतमपुरा, नई दिल्ली को फर्जी फर्म रैकेट चलाने तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल मामले में गिरफ्तार किया गया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की वास्तव में आपूर्ति ही नहीं हुई थी। यह भी पाया गया है कि मनीष मोदी फर्जी फर्मों मेसर्स निवारण एंटरप्राइजेज और मेसर्स पंचवटी एंटरप्राइजेज का प्रबंधन/नियंत्रण कर रहे थे और इनके आधार पर मनीष ने 36 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी बिल पेश किए।

देश में एक ही दिन में बढ़े 12 हजार से ज्यादा मामले

» पिछले 24 घंटे में 37,593 नए मरीज, 648 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण लगातार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। एक दिन बाद ही 12 हजार से ज्यादा नए मामलों में बढ़ोतरी ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए, तो वहीं संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 648 तक दर्ज किया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को कोरोना के मामले में मंगलवार के मुकाबले 12 हजार से अधिक की वृद्धि आम लोगों के साथ ही सरकार के लिए भी किसी चिंता से कम नहीं है। पिछले एक दिन में जहां नए मामलों और इस संक्रमण से मौतों को आंकड़ा बढा है, वहीं इस दौरान कोरोना के 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। अब मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.67 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 2,776 की बढ़ोतरी के बाद देश में सक्रीय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,22,327 हो गई है। देश में अब तक कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,17,54,281 हो गई है। जबकि कोरोना संक्रमण से देश में अब तक 4,35,758 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर देश में पिछले एक दिन में 63.85 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, जिसके बाद देश में बुधवार को सुबह तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 59.55 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से अभी तक कुल 4,35,758 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,36,355, कर्नाटक के 37,184, तमिलनाडु के 34,761, दिल्ली के 25,079, उत्तर प्रदेश के 22,794, केरल के 19,757 और पश्चिम बंगाल के 18,383 लोग थे।

केरल में सर्वाधिक मामले

मंत्रालय के अनुसार केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए हैं। जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,51,984 हो गई। जबकि 173 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 19,757 पर पहुंच गई। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.99 फीसदी हैं।वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.10 फीसदी है, दैनिक पॉजिटिविटी रेट पिछले 30 दिनों से 3 फीसदी से कम है। वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर 1.92 प्रतिशत है, जो पिछले 61 दिन से तीन प्रतिशत से कम है। देश में अभी तक कुल 51,11,84,547 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 17,92,755 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई।

ऐसे चला कोरोना संक्रमण का ग्राफ- देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे। आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे जिन 648 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 288 और केरल के 173 लोग थे।

शांतिकुंज की स्थापना के पचास वर्ष पूरे होने पर स्थापित होंगे स्वर्ण जयंती वन

हरिद्वार (आरएनएस)। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांतिकुंज की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में पचास स्थानों पर स्वर्ण जयंती वनों की स्थापना की जाएगी। शांतिकुंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे देश में 50 स्थानों पर स्वर्ण जयंती वनों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत एक साथ व एक समय पर तरु -पुत्र रोपण महायज्ञ के माध्यम से हजारों स्थानों पर सामूहिक वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही जिन घरों में आंगन या छत उपलब्ध है। वहां माता भगवती की बाड़ी, ग्रीन जोन ,गमलों में स्वास्थ्य वाटिका, लघु आरोग्य वाटिका भी स्थापित की जाएगी। कोविड-19 में दिवंगत परिजनों की स्मृति में वृक्षारोपण, अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ की स्मृति में वृक्षारोपण तथा छतों पर शाक वाटिका लगाने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का ऑनलाइन संचालन शांतिकुंज से किया जाएगा। गायत्री परिवार के प्रमुख डा.प्रणव पंडया ने बताया कि शांतिकुंज नवयुग के निर्माण की गंगोत्री बनकर उभरा है। व्यक्ति परिवार और समाज राष्ट्र के नव निर्माण हेतु विभिन्न साधनात्मक, प्रचारात्मक, सुधारात्मक और रचनात्मक कार्यों का निरंतर संचालन शांतिकुंज से किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष दो हजार से वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत पूरे देश में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पौधों को पुत्र या मित्र रूप में गोद लेकर उन्हें स्मृति वन -उपवन में रोपित कर पालन पोषण किया जाता है। इस प्रकार अभी तक 250 से अधिक छोटी- बड़ी पहाड़ियों व मैदानों को हरा-भरा बनाया गया है। 2011 से अब तक 2 करोड़ से अधिक वृक्षों का रोपण किया जा चुका है।

रेलवे परियोजना में जल्द दूर हो सकती है अड़चनें

» सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियों को गिराने पर यथास्थिति आदेश एक सितंबर तक बढ़ाया

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में एक रेल लाइन परियोजना के लिए करीब 5,000 झुग्गियों को हटाए जाने पर यथास्थिति बनाए रखने का अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश बुधवार को एक सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इससे पहले यह मामला तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। यह मामला बुधवार को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पीठ से कहा कि वह प्राधिकरण से निर्देश लेने की प्रक्रिया में हैं और मामले की दो दिन बाद सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बीच मामले में पारित अंतरिम आदेश कायम रह सकता है। मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह भी यही अनुरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध के अनुसार, मामले को एक सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कल प्रधान न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था।

जल्द बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत

» इसी साल मिल सकता है रूस का एस-400 मिसाइल रक्षा सिस्टम

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत को साल 2023 तक रूस में निर्मित क्रिवाक श्रेणी का पहला जंगी जहाज मिल जाएगा। यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन (यूएससी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी रखमानोव ने यह भरोसा दिलाया। इसके अलावा भारत को इस साल के आखिर तक रूसी मिसाइल रक्षा सिस्टम एस-400 भी मिलने की उम्मीद है।

मॉस्को में आयोजित 'आर्मी-2021' को संबोधित करते हुए रखमानोव ने कहा, 'कोरोना संकट के चलते क्रिवाक श्रेणी के जहाज के निर्माण में कुछ अड़चनें आई। यह प्रोजेक्ट लगभग आठ महीने पीछे चल रहा है। भारत को 2023 के मध्य तक दो में से एक जहाज सौंप दिया जाएगा। रूसी अधिकारी ने बताया कि यानतार बंदरगाह पर जहाज के निर्माण में योगदान देने के लिए भारतीय तकनीशियनों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इससे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में क्रिवाक श्रेणी के दो जंगी जहाज के निर्माण की भावी योजना को साकार करने में मदद मिलेगी। रखमानोव ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय तकनीशियन जहाज बनते देखें, ताकि वे इसकी तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें। इससे दूसरे चरण के तहत गोवा शिपयार्ड में जहाज का निर्माण आसान हो जाएगा। भारतीय तकनीशियन न सिर्फ कलपुर्जे जोड़ने, बल्कि प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने में भी सक्षम बन पाएंगे।

एस-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति इस साल- रूस साल 2021 के अंत तक भारत को एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर देगा। रूसी कंपनी 'अलमाज-आंते' के सीईओ व्याचेशलव जिरकाल्न ने सोमवार को मॉस्को में आयोजित 'आर्मी-2021' में यह जानकारी दी। जिरकाल्न ने कहा कि एस-400 का निर्माण निर्धारित समय पर आगे बढ़ रहा है।

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को दी सौगात

» एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के हक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आज कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस(एफआरपी) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है, ये 10 फीसदी रिकवरी पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5 फीसदी से कम होती है तो उन्हें 275.50 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। गौरतलब है इससे पहले गन्ने का एफआरपी 285 रुपये प्रति क्विंटल था यानी कि इसबार पांच रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। सरकार हर साल गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार एफआरपी की घोषणा करती है। मिलों को यह न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादकों को देना होता है।

गन्ना किसानों को 86 हजार करोड़ रुपये का भुगतान - केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2020-21 में गन्ना किसानों को 91,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था जिसमें 86,000 करोड़ का भुगतान हो गया है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण अब गन्ना किसानों को पहले की तरह सालों-साल अपने भुगतान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज के इस फैसले के बाद किसानों को उनके खर्च पर 87 फीसदी का रिटर्न होगा। एफआरपी के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गन्ना किसानों को बाकी सब फसलों से ज्यादा दाम मिले।

क्या है एफआरपी?- एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज (सीएसीपी) हर साल एफआरपी की सिफारिश सरकार से करता है। सीएसीपी गन्ना सहित प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिश भेजती है। उस पर विचार करने के बाद सरकार उसे लागू करती है। हालांकि एफआरपी सभी किसानों पर लागू नहीं होता है। गन्ना का अधिक उत्पादन करने वाले कई बड़े राज्य गन्ना की अपनी-अपनी कीमतें तय करते हैं। इसे स्टेट एडवायजरी प्राइस (एसएपी) कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अपने राज्य के किसानों के लिए अपना एसएपी तय करते हैं। आम तौर पर एसएपी केंद्र सरकार के एफआरपी से ज्यादा होता है।

भारत-कजाकिस्तान सेनाओं का संयुक्त अभ्यास 30 अगस्त से

नईदिल्ली (आरएनएस)। कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में 'भारत-कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वां संस्करण' ट्रेनिंग नोड, आइशा बीबी, कजाकिस्तान में 30 अगस्त से 11 सितम्बर, 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन करेगी, जिसमें एक टुकड़ी कमांडर की अगुवाई में कुल 90 सैन्य कर्मी शामिल हैं और कजाकिस्तान सेना का एक प्रतिनिधित्व एक कंपनी समूह द्वारा किया जाएगा। यह सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद निरोधी अभियानों में दक्ष करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेशेवर रणनीतिक कौशल, उप इकाई स्तर पर आतंकवाद विरोधी माहौल में अभियानों की योजना और उनके क्रियान्वयन, हथियार चलाने संबंधी कौशल और आतंकवाद तथा उग्रवाद संबंधी अभियानों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी पर खरीदी से लगभग 129.03 लाख किसान हुए लाभान्वित

नईदिल्ली (आरएनएस)। धान की खरीद खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। लगभग 129.03 लाख किसान मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 1,64,951.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 23 अगस्त तक 873.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 707.69 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 165.99 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 763.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।

गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले राज्यों में पूरा हो चुका है। अब तक 433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी (जो कि अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है, क्योंकि इसने आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर 389.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है), जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 389.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।

लगभग 49.20 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85603.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 109.58 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई थी। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।

खरीफ 2020-21 और रबी 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत 23.08.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 11,91,926.47 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के 6,96,803 किसानों को 6,686.59 करोड़ रुपये की आय हुई है।